नईदुनिया

किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताः चौहान

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय और सुरक्षा बढ़ाने को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे तंबाकू जैसी हानिकारक फसलों की जगह लाभदायक फसलों को बढ़ावा देना, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद, फसल बीमा योजना में सुधार और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करना।

संसद के निचले सदन में सांसदों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों से तंबाकू की खेती छोड़ने की अपील की है और इसके बदले कई फायदे वाली फसलों की पहचान की है। इनमें हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, आलू, चिया, फीड बीन्स, लोबिया, रागी, अरहर, गन्ना, सोयाबीन, ज्वार और मूंगफली जैसी फसलें शामिल हैं, ताकि किसानों की नकद आय सुरक्षित बनी रहे।

मंत्री ने कहा कि देश के ज्यादातर किसानों के पास छोटी जमीन होती है, इसलिए केवल एक ही फसल पर निर्भर रहना जोखिम भरा होता है। इसको देखते हुए सरकार ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग (मिश्रित खेती) के कई मॉडल तैयार किए हैं, जिनका अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इन मॉडलों के तहत किसान अनाज (गेहूं और धान), सब्जियां, फल, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन और एग्रो-फॉरेस्ट्री जैसी गतिविधियों को एक साथ अपना सकते हैं। इससे उन्हें पूरे साल स्थिर और ज्यादा आय मिल सकती है।

चौहान ने आगे बताया कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाया गया है और इस सीजन में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने दालों जैसे तूर, मसूर और उड़द के लिए भी व्यवस्था की है, जिसमें किसान रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पूरी उपज बेच सकते हैं और सरकार उसे खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे दाल उत्पादक किसानों को बड़ा सहारा मिला है।

फसल बीमा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि पहले किसानों को मुआवजा पाने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिससे अगर किसी एक किसान की फसल भी खराब होती है तो उसे मुआवजा मिलना जरूरी होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि अगर 21 दिनों के भीतर बीमा राशि किसान के खाते में नहीं आती है, तो बीमा कंपनी और राज्य सरकार को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। इससे किसानों को देरी का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है और फसल बीमा या अन्य योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि रक्षक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जहां भी अनियमितता पाई जाती है, वहां दोषियों पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में राजस्थान सहित कई राज्यों में फसल बीमा के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजे गए हैं, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिला है।

वित्त मंत्री ने पीएम मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायों को मिले लाभ और वृद्धि की जानकारी दी

पीएम मुद्रा योजना से छोटे उद्यमियों को मिल रही सशक्तिकरण की ताकतः सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश के छोटे उद्यमियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है, जिससे लाखों लोग अपने बिजनेस आइडिया को आसानी से शुरू कर पा रहे हैं।

राज्यसभा में योजना के प्रभाव से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के लोन दिए जाते हैं - शिशु (50,000 रुपए तक), किशोर (50,001 से 5 लाख रुपए तक) और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपए तक)। ये तीनों कैटेगरी अलग-अलग स्तर के कारोबार के लिए हैं, जिससे छोटे और माइक्रो बिजनेस को बढ़ावा मिलता है।

31 मार्च 2025 तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, शिशु कैटेगरी में 12.4 प्रतिशत, किशोर में 9.4 प्रतिशत और तरुण में 7.92 प्रतिशत लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में दर्ज हैं। बैंकों द्वारा इन लोन की वसूली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि योजना को लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जा सके।

वित्त मंत्री ने तरुण प्लस कैटेगरी को लेकर भी बात की,

जिसमें 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है। यह योजना खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले लिए गए तरुण लोन को समय पर चुका दिया है और अब अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहते हैं।

यह नई कैटेगरी केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद शुरू की गई थी और अक्टूबर 2024 से लागू हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि यह योजना अभी नई है, इसलिए इसके सही असर को देखने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है।

2015 में शुरू हुई पीएम मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन भी स्वीकृत किए गए हैं।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा महिला उद्यमियों को मिला है, क्योंकि कुल लोन में से करीब 68 प्रतिशत लोन महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

सरकार छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि आत्मनिर्भर भारत और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब वित्तीय क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हो रही है। आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई सेक्टर का कुल एनपीए मार्च 2025 तक करीब 3.6 प्रतिशत रहा, जो मुद्रा योजना के आंकड़ों से कम है।

जनजातीय होमस्टे मालिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

नयी दिल्ली। भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनजातीय होमस्टे मालिकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह पहल जनजातीय समुदायों द्वारा संचालित होमस्टे के पेशेवर आतिथ्य कौशल को सुदृढ़ करने, सेवा मानकों को सुधारने और आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन आईएचएम अशोक द्वारा किया गया। पहले बैच में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गुजरात से आए 40 प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम में होमस्टे संचालकों को आतिथ्य प्रबंधन, पर्यटक सेवा, स्वच्छता, स्थानीय संस्कृति के प्रस्तुतीकरण और टिकाऊ पर्यटन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ट्राइबल होमस्टे - जनजातीय आवास संचालन एवं विकास नियमावली 2026 का विमोचन भी किया गया, जो जनजातीय होमस्टे के पेशेवर प्रबंधन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि आजकल के पर्यटक प्रदूषण मुक्त, प्रकृति के करीब और कम भीड़-भाड़ वाले स्थानों में ठहरना पसंद करते हैं, और होमस्टे मॉडल एक प्रभावी पर्यटन विकल्प बनकर उभर रहा है।

वैश्विक तनावों के बीच सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी में 3,600 रुपए की तेजी

मुम्बई। वैश्विक तनावों के कारण कीमती धातुओं की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव हो रहा है। 17 मार्च 2026 को, सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखी गई, जबकि चांदी की कीमत में तेजी आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के अनुसार, 999 प्यूरिटी वाला सोना 46 रुपए घटकर 1,55,668 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 3,629 रुपए बढ़कर 2,52,340 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी दोनों धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव था। अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 0.36 प्रतिशत बढ़कर 1,56,293 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि मई डिलीवरी वाली चांदी 0.07 प्रतिशत बढ़कर 2,56,716 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतें 1,55,000-1,56,000 रुपए के समर्थन स्तर से ऊपर बनी रहें तो मध्य अवधि में तेजी का रुझान बरकरार रह सकता है। वहीं, चांदी की कीमत में 2,65,000 रुपए के ऊपर बढ़ोतरी होने पर यह 2,75,000 से 2,80,000 रुपए तक जा सकती है।

हाल के महीनों में कीमती धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण हुई है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है, जो इन कीमतों को प्रभावित कर सकता है।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय परिवारों की बचत बढ़कर जीडीपी की 21.7 प्रतिशत हुईः पंकज चौधरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में जानकारी दी कि नई जीडीपी सीरीज (बेस ईयर 2022-23) के अनुसार, भारतीय परिवारों की बचत वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर जीडीपी के 21.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 20 प्रतिशत थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में कहा कि घरेलू परिवारों की बचत अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत है, जो परिवारों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई नीतिगत सुधारों के माध्यम से परिवारों की आय और बचत में निरंतर वृद्धि की उम्मीद जताई है। इनमें व्यापार करने में सुगमता में सुधार, कौशल विकास पहलों का विस्तार, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में किए गए नीतिगत कदम, जैसे 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट और जीएसटी दरों का युक्तिकरण, से व्यय योग्य आय में वृद्धि की संभावना है, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में खाद्य और ईंधन में महंगाई नहीं थी, और खुदरा खाद्य कीमतों में 2024-25 के मुकाबले 0.98 प्रतिशत की कमी आई।

खाद्य तेल, चीनी के दाम बढ़े; गेहूं नरम; दालों में उतार-चढ़ाव

नयी दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को गेहूं की औसत कीमत में कमी आई, जबकि चावल का भाव स्थिर रहा। खाद्य तेलों और चीनी के दाम बढ़े, वहीं दालों में उतार-चढ़ाव का रुख देखा गया।

चावल की औसत कीमत 3,850 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रही, जबकि गेहूं नौ रुपये सस्ता होकर 2,803 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा था। आटा भी आठ रुपये घटकर बिक रहा था। दालों में तुअर दाल की कीमत 26 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी, उड़द दाल भी 18 रुपये महंगी हुई, जबकि मसूर और मूंग दाल की कीमतों में गिरावट आई। चना दाल भी आठ रुपये सस्ती हुई। विदेशी बाजारों में, मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का जून वायदा 71 रिंगिट गिरकर 4,583 रिंगिट प्रति टन हो गया, जबकि अमेरिकी सोया तेल का वायदा 2.60 प्रतिशत बढ़कर 65.65 सेंट प्रति पौंड हो गया। स्थानीय बाजारों में पाम ऑयल की औसत कीमत 65 रुपये, सूरजमुखी तेल की 52 रुपये और सोया तेल और सरसों तेल की 26-26 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई। मूंगफली तेल 25 रुपये और वनस्पति तेल तीन रुपये महंगा हुआ। गुड़ का औसत भाव 24 रुपये प्रति क्विंटल घटा, जबकि चीनी तीन रुपये महंगी हुई।

रुपया 12 पैसे टूटा, नये निचले स्तर पर

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को 11.75 पैसे कमजोर हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 92.40 रुपये बोला गया। यह भारतीय मुद्रा का रिकॉर्ड निचला स्तर है। पिछले कारोबारी दिवस पर यह 1.75 पैसे की मजबूती के साथ 92.2825 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी।

रुपया आज शुरू से ही दबाव में रहा। यह 6.75 पैसे टूटकर 92.35 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और पूरे दिन सीमित दायरे में रहा। यह ऊपर 92.35 रुपये और नीचे 92.4775 रुपये प्रति डॉलर तक गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में करीब दो प्रतिशत की तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारतीय पूंजी बाजार में बिकवाल रहने से रुपये पर दबाव रहा। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर में नरमी से भारतीय मुद्रा को समर्थन मिला।

मारुति सुजुकी इंडिया को मिला 5,786 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसे इनकम टैक्स से एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला है, जिसमें 5,786 करोड़ रुपए की डिमांड शामिल है।

हालांकि, कंपनी ने कहा कि इस नोटिस का उसकी वित्तीय स्थिति और ऑपरेशनल प्रदर्शन पर कोई असर नहीं होगा। रेगुलेटरी फाइलिंग में ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने कहा कि वह उचित प्रक्रिया के तहत विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगी।

असेसमेंट ऑर्डर में वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित है, जिसमें कर अधिकारियों ने कंपनी की रिपोर्ट की गई आय में 57,864 मिलियन रुपए की कुछ बढ़ोतरी और कटौती का प्रस्ताव दिया है। ऑटो कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्राप्त हुआ है,

जिसमें आयकर रिटर्न में घोषित आय (कंपनी द्वारा आयकर रिटर्न में बताई गई आय) के संबंध में 57,864 मिलियन रुपए की कुछ अतिरिक्त राशि/अस्वीकरण प्रस्तावित किए गए हैं।

कंपनी ने आगे कहा, विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करेगी। इस डेवलपमेंट के बाद भी मारुति सुजुकी के शेयर में तेजी देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर शेयर 1.98 प्रतिशत की तेजी के साथ 13,010 रुपए पर बंद हुआ।

साथ ही, कंपनी ने अपने हालिया वित्तीय प्रदर्शन का विवरण भी साझा किया। अपने अनऑडिटेड तीसरी तिमाही के परिणामों के अनुसार, मारुति सुजुकी इंडिया ने कुल कर व्यय 10,360 मिलियन रुपए दर्ज किया।

कंपनी की बिक्री 6,67,769 मिलियन रुपए रही, जबकि कर पश्चात लाभ (पीएटी) 37,940 मिलियन रुपए रहा।

परिचालन के लिहाज से, कंपनी ने स्थिर वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में, मारुति सुजुकी ने 1,435,945 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

बिक्री में मिनी कार, कॉम्पैक्ट वाहन, मिडसाइज कार और यूटिलिटी वाहन शामिल थे। भविष्य में कंपनी मांग को लेकर सतर्क रूप से आशावादी बनी हुई है। वरिष्ठ कार्यकारी राहुल भारती ने पहले संकेत दिया था कि चौथी तिमाही सकारात्मक रहने की उम्मीद है, साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में विकास का स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आएगा।

लगातार दूसरे दिन बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 568 अंक उछला

मुंबई। पिछले कई तीन दिनों की गिरावट के बाद हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे सत्र में तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ।

इस दौरान, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 0.75 प्रतिशत या 568 अंक बढ़कर 76,070.84 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी50 0.74 प्रतिशत या 172.35 अंक बढ़कर 23,581.15 पर बंद हुआ।

दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने जहां 75,826.68 पर खुलकर 76,304.26 के उच्चतम स्तर को छुआ, वहीं निफ्टी ने 23,493.20 पर खुलकर 23,656.80 का उच्चतम स्तर छुआ।

मंगलवार के सत्र में समग्र बाजार में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप में 1.02 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.65 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सेक्टरवार देखें तो, निफ्टी ऑटो (2.11 प्रतिशत) और निफ्टी मेटल (2.82 प्रतिशत) सबसे आगे रहे, जबकि निफ्टी आईटी (0.97 प्रतिशत) और निफ्टी एफएमसीजी (0.75 प्रतिशत) में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। सत्र के दौरान इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स (इंडिया वीआईएक्स) 9.12 प्रतिशत गिरकर 19.63 पर आ गया और अंत में यह 8.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19.79 पर बंद हुआ।

निफ्टी50 इंडेक्स में इटरनल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, बीईएल, मारुति सुजुकी, एलएंडटी, भारती एयरटेल और ओएनजीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली और ये टॉप गेनर्स में शामिल रहे। वहीं इसके विपरीत विप्रो, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंफोसिस, आईटीसी और बजाज फाइनेंस के शेयर टॉप लूजर्स में शामिल रहे।

मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर निफ्टी 23,600 के ऊपर मजबूती से टिकता है तो यह 23,800 से 24,000 के स्तर तक जा सकता है। हालांकि, यह रेंज आगे चलकर मजबूत रेजिस्टेंस (बिकवाली का दबाव) भी बन सकती है। दूसरी तरफ, अगर बाजार ऊपर के स्तर पर टिक नहीं पाता है तो यह फिर से 23,500 तक आ सकता है और इसके नीचे 23,300-23,350 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट देखने को मिल सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूती दिखी है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से ट्रेंड बदलने का संकेत नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिलहाल एक रिकवरी (सुधार) का दौर है, जिसमें चुनिंदा सेक्टरों में ही ज्यादा खरीदारी हो रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते आगे भी बाजार में सावधानी के साथ हल्की तेजी का रुख बना रह सकता है।

भारत में पेश हुई नया रेनो डस्टर कीमत 10.49 लाख रुपये से

नयी दिल्ली। रेनो इंडिया ने मंगलवार को देश में नये रेनो डस्टर को बाजार में पेश करने की घोषणा की जिसकी कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू हो रही है।

फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनो समूह की कंपनी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि रेनो डस्टर के टर्बो मॉडल की दिल्ली में एक्स शो-रूम कीमत 10.49 लाख रुपये होगी। कंपनी ने बताया कि इसे भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

टर्बो टीसीई 100 को तीन संस्करणों ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन और टेक्नो में पेश किया गया है। इनकी कीमत 10.49 लाख रुपये से 13.49 लाख रुपये तक है।

टर्बो टीसीई 160 को चार संस्करणों इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आईकॉनिक में पेश किया गया है। इनकी कीमत 12.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये तक है।

टर्बो टीसीई 160 डीसीटी को भी इन्हीं चार संस्करणों में 14.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये की रेंज में बाजार में उतारा गया है।

सभी संस्करणों के लिए 31 मार्च तक खरीदने पर 20 हजार रुपये से 40 हजार रुपये तक की विशेष छूट की घोषणा की गयी है।

कंपनी ने बताया है कि नये डस्टर की लंबाई 4.346 मीटर, चौड़ाई 1.815 मीटर और ऊंचाई 1.701 मीटर है। जमीन से क्लियरेंस 21.2 सेंटीमीटर है। ईंधन टैंक की क्षमता 50 लीटर है।

जियो पेमेंट्स बैंक ने शुरू की यूपीआई आधारित नकद निकासी सेवा

मुंबई। जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (जेपीबीएल) ने मंगलवार को यूपीआई आधारित नकद निकासी सेवा शुरू करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया कि ग्राहक अब बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टचपॉइंट्स पर क्यूआर कोड स्कैन कर नकद निकाल सकेंगे। उन्हें अपना पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड या पारंपरिक एटीएम कार्ड की अब जरूरत नहीं होगी।

बैंक के अनुसार, नयी सेवा विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर शुरू की गयी है, जहां एटीएम की पहुंच सीमित है। ग्राहक अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से अपने लेनदेन को ऑथराइज कर आसानी से नकद प्राप्त कर सकेंगे।

जियो पेमेंट्स बैंक ने कहा कि बिना कार्ड नकद निकासी सुविधा से डिजिटल भुगतान और नकद उपयोग के बीच की दूरी कम होगी। इससे पहली बार डिजिटल भुगतान अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सहायक वातावरण में यूपीआई अनुभव मिल सकेगा। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपनी डिजिटल भुगतान अवसंरचना और अंतिम छोर पर स्थित बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क की मदद से यह पहल देश में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, नकद पर निर्भर वर्गों तक यूपीआई का विस्तार करने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

स्पेशल खबर एनपीसीआई ने श्रीलंका में यूपीआई स्वीकार्यता का विस्तार किया, भारतीय पर्यटकों को मिलेगा फायदा

एनपीसीआई और लंकापे के सहयोग से श्रीलंका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अंतरराष्ट्रीय इकाई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड (एनआईपीएल) ने मंगलवार को कहा कि वह श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की स्वीकार्यता में विस्तार कर रहा है।

एनपीसीआई ने आगे कहा कि इससे भारतीय यात्रियों के लिए श्रीलंका में भुगतान का अनुभव अच्छा होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

भारत में 700 मिलियन से अधिक क्यूआर टचपॉइंट्स के साथ, प्लेटफॉर्म की इंटरऑपरेबल आर्किटेक्चर वैश्विक प्रणालियों के साथ एकीकरण को सक्षम बनाती है, जिसमें श्रीलंका का लंकापे-संचालित लंकाक्यूआर इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। पर्यटन क्षेत्र के लिए भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा स्रोत बाजार बना हुआ है। 2024 में 4.16 लाख से अधिक भारतीय पर्यटकों श्रीलंका गए थे, यह आंकड़ा 2025 में बढ़कर 5.31 लाख हो गया। इस स्थिर वृद्धि ने घूमने, खरीदारी, शादियों और आध्यात्मिक

पर्यटन के लिए द्वीप पर आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए सुविधाजनक और विश्वसनीय भुगतान समाधानों की मांग को बढ़ा दिया है।

एनपीसीआई ने कहा, एनआईपीएल और लंकापे के बीच सहयोग के माध्यम से, भारतीय पर्यटक अब यूपीआई-सक्षम ऐप का उपयोग करके लंकाक्यूआर कोड को स्कैन करके पूरे श्रीलंका में डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हो जाएगी।

यह सेवा प्रमुख प्रतिष्ठानों, जिनमें होटल चेन, खुदरा दुकानें और सुपरमार्केट शामिल हैं, में उपलब्ध है। इस सेवा की व्यापक स्वीकृति के लिए, एनआईपीएल श्रीलंका के घरेलू भुगतान ढांचे के अनुरूप, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक, अधिग्रहण करने वाले बैंकों और व्यापारियों जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एनपीसीआई के अनुसार, इस पहल से यात्रियों और व्यापारियों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है। पर्यटकों को वास्तविक समय में भुगतान, पारदर्शी विनिमय दरें और एक परिचित भुगतान इंटरफेस की सुविधा मिलेगी, वहीं श्रीलंकाई व्यवसाय एक बड़े डिजिटल ग्राहक आधार का लाभ उठा सकेंगे, नकदी प्रबंधन में सुधार कर सकेंगे और भौतिक मुद्रा पर निर्भरता कम कर सकेंगे।

एनपीसीआई इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा कि कंपनी सीमा पार लेनदेन को सरल बनाने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अंतर-संचालनीय भुगतान गलियारों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा, यूपीआई के बढ़ते उपयोग के साथ, हमारा लक्ष्य आतिथ्य, खुदरा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भुगतान स्वीकृति को बढ़ाना है, जिससे व्यवसायों के लिए मूल्य सृजित हो और समग्र यात्रा अनुभव बेहतर हो।